RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 28 फरवरी से 7 मार्च 2026 | भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष - 13 | अंक-81 | पृष्ठ-11 | मुल्य- रू. 5/-

आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं पर कड़े नियम लागू किए

बोर्ड-अनुमोदित नीति अनिवार्य, नए लोन पर सख्ती; एनबीएफसी की एसेट क्वालिटी और जोखिम प्रबंधन में सुधार का लक्ष्य

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं, जिनके तहत डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं को नए लोन देने से पहले बोर्ड-अनुमोदित स्पष्ट नीति बनानी होगी। यह कदम एनबीएफसी सेक्टर में बढ़ते जोखिमों और एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।

आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि एनबीएफसी को उन उधारकर्ताओं के लिए अलग से नीति तैयार करनी होगी, जिन्होंने किसी भी एनबीएफसी या बैंक में डिफॉल्ट किया हो या जिनके खाते एनपीए घोषित किए गए हों। यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए और इसमें नए लोन देने की शर्तें, क्रेडिट रिस्क मूल्यांकन और निगरानी के प्रावधान शामिल होने चाहिए। नियमों का पालन न करने पर एनबीएफसी पर जुर्माना या अन्य नियामक कार्रवाई हो सकती है।

यह कदम ऐसे समय आया है जब एनबीएफसी सेक्टर में अनसिक्योर्ड लेंडिंग और डिजिटल लोन में तेज वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ मामलों में डिफॉल्ट दर बढ़ी है। आरबीआई गवर्नर ने हाल ही में कहा था कि एनबीएफसी को जोखिम प्रबंधन पर और सख्ती बरतनी होगी। नए नियमों से एनबीएफसी को उधारकर्ताओं की क्रेडिट हिस्ट्री की गहन जांच करनी होगी, जिससे एनपीए में कमी आएगी और सेक्टर की स्थिरता बढ़ेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियम एनबीएफसी की एसेट क्वालिटी सुधारने में मदद करेगा, लेकिन लोन प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है। छोटे उधारकर्ताओं और MSME को भी इसका असर महसूस हो सकता है। आरबीआई का यह कदम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

होर्मुज स्ट्रेट में संकट गहराया: अमेरिका ने ईरानी युद्धपोत पर हमला किया, टैंकर फंसे

ईरान-इजरायल तनाव के बीच जलमार्ग बंदी की आशंका, वैश्विक तेल आपूर्ति पर खतरा; भारत के लिए ऊर्जा संकट की चेतावनी, कीमतें आसमान छू सकती हैं

भोपाल: होर्मुज स्ट्रेट में संकट और गहरा गया है। अमेरिका ने ईरानी नौसेना के एक युद्धपोत पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने इस क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। इस वजह से दर्जनों तेल टैंकर और अन्य मालवाहक जहाज फंस गए हैं। यह जलमार्ग दुनिया के 20% से अधिक तेल और गैस का रास्ता है, और इसकी बंदी से वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल मच गई है।

अमेरिकी नौसेना ने दावा किया कि हमला ईरानी जहाज द्वारा अमेरिकी जहाजों पर खतरा पैदा करने के जवाब में किया गया। ईरान ने इसे 'आक्रामक कार्रवाई' बताया और जवाबी हमले की चेतावनी दी है। इस तनाव से होर्मुज में जहाजों का आवागमन लगभग रुक गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 8% से अधिक उछलकर 95 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं।

भारत के लिए यह बड़ा खतरा है, क्योंकि भारत अपनी 60% से अधिक तेल जरूरत होर्मुज से आने वाले जहाजों पर निर्भर करता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर संकट लंबा चला तो पेट्रोल-डीजल की कीमतें 10-15 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकती हैं। भारत सरकार ने वैकल्पिक रास्तों और रणनीतिक भंडार का उपयोग करने की तैयारी शुरू कर दी है।

विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। भारत को अब अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से तेल आयात बढ़ाने की जरूरत है। यह संकट भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस को और तेज कर सकता है।

MRF तमिलनाडु में 5,300 करोड़ रुपये का नया टायर प्लांट लगाएगी

2 करोड़ यूनिट सालाना क्षमता, 2028 तक उत्पादन शुरू; ट्रक-बस और पैसेंजर टायर पर फोकस, 2,000+ रोजगार सृजन

चेन्नई: भारत की सबसे बड़ी टायर कंपनी MRF लिमिटेड ने तमिलनाडु में 5,300 करोड़ रुपये के नए टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना की घोषणा की है। यह प्लांट तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में लगाया जाएगा, जहां सालाना 2 करोड़ यूनिट्स टायर का उत्पादन होगा। कंपनी ने राज्य सरकार के साथ MoU साइन किया है और प्लांट 2028 तक चालू होने की उम्मीद है।

MRF के चेयरमैन के. एम. मुथैया ने कहा, यह निवेश हमारी क्षमता बढ़ाने और घरेलू-निर्यात बाजार की मांग पूरी करने के लिए है। हम ट्रक-बस रेडियल टायर, पैसेंजर कार टायर और दोपहिया टायर पर फोकस करेंगे। प्लांट में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रोसेस का उपयोग होगा, जिससे ईंधन दक्षता और पर्यावरण अनुकूल टायर बनेंगे।

यह प्लांट 2,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और हजारों अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित करेगा। तमिलनाडु सरकार ने कंपनी को भूमि, टैक्स छूट और अन्य सुविधाएं देने का आश्वासन दिया है। राज्य का ऑटोमोटिव और टायर सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, जहां MRF पहले से ही चेन्नई और तिरुचिरापल्ली में बड़े प्लांट चला रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश भारत के ऑटो टायर बाजार में MRF की स्थिति को और मजबूत करेगा। देश में दोपहिया और कमर्शियल वाहनों की मांग बढ़ रही है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक अपनी कुल क्षमता 25 करोड़ यूनिट्स सालाना तक ले जाना है। यह कदम 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत के विजन को समर्थन देगा।

Shriram Finance Secures USD 76 Million Co-Financing for Economic Inclusion & Rural Development

Partnership with International Lenders to Expand Affordable Credit in Underserved Areas; Targets 5 Million+ New Borrowers in Next 3 Years

Chennai: Shriram Finance Ltd, one of India's largest non-banking financial companies (NBFCs), has secured USD 76 million (approximately ₹640 crore) in co-financing from a consortium of global development institutions to support its economic inclusion and rural development initiatives. The funding, led by the International Finance Corporation (IFC) and supported by the Asian Development Bank (ADB) and other impact investors, will be used to extend affordable credit to micro, small, and medium enterprises (MSMEs), rural households, and women borrowers in underserved regions.

The facility carries concessional terms and long-tenure funding, enabling Shriram Finance to offer lower interest rates and longer repayment periods to priority segments. The company plans to deploy the funds across its extensive network of over 3,000 branches, with a special focus on Tier-2, Tier-3 cities, and rural districts in states like Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Tamil Nadu.

Shriram Finance Managing Director Umesh Revankar said, this partnership aligns perfectly with our mission to bridge the credit gap for millions of unbanked and underbanked Indians. The concessional funding will help us scale our vehicle finance, MSME loans, and small-ticket personal loans while maintaining strong asset quality.

The co-financing is expected to benefit over 5 million new borrowers in the next three years, particularly women entrepreneurs, small farmers, and first-time borrowers in rural areas. It also supports Shriram's broader ESG commitments, including financial inclusion, gender equality, and sustainable rural livelihoods.

The deal comes at a time when NBFCs are playing an increasingly important role in India's financial inclusion journey, especially after recent regulatory tightening on unsecured lending. Analysts view the funding as a positive signal of continued international confidence in India's NBFC sector and Shriram's robust risk management.

As India targets deeper financial inclusion and rural credit penetration, such partnerships are expected to accelerate progress toward a more equitable and resilient economy.

फरवरी में भारतीय रिटेल ऑटो बिक्री 25.6% उछली, कुल वाहन बिक्री 24 लाख पहुंची: FADA

त्योहारी सीजन और ग्रामीण मांग से SUV-दोपहिया में जोरदार तेजी, FY26 में रिकॉर्ड ग्रोथ की उम्मीद; मारुति, हुंडई और टाटा ने बाजार पर कब्जा मजबूत किया

नई दिल्ली: फरवरी 2026 में भारतीय ऑटोमोबाइल रिटेल बिक्री में 25.6% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) के आंकड़ों के अनुसार, इस महीने कुल 24 लाख वाहनों की रिटेल बिक्री हुई, जो पिछले साल की समान अवधि से काफी अधिक है। यह वृद्धि त्योहारी सीजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और SUV सेगमेंट की मजबूत मांग से प्रेरित रही।

पैसेंजर व्हीकल्स (PV) की बिक्री में 22% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें SUV की हिस्सेदारी 52% से अधिक रही। मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स ने इस सेगमेंट में बाजार पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। दोपहिया वाहनों की बिक्री में 28% की उछाल आई, जो ग्रामीण और छोटे शहरों में मोटरसाइकिल की मांग बढ़ने से हुई।

कमर्शियल व्हीकल्स में भी 18% ग्रोथ दर्ज हुई, जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की रिकवरी को दर्शाती है।

FADA के प्रेसिडेंट ने कहा, "फरवरी में त्योहारी मांग और ग्रामीण क्रय शक्ति में सुधार से बाजार में जबरदस्त तेजी आई। FY26 में कुल बिक्री 3.5-4 करोड़ यूनिट्स तक पहुंच सकती है।" हालांकि, उच्च ब्याज दरों और ईंधन कीमतों ने मध्यम वर्ग की खरीदारी पर कुछ असर डाला।

विशेषज्ञों का मानना है कि SUV और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग से सेक्टर की ग्रोथ 2026 में भी मजबूत रहेगी। ऑटो कंपनियां नए मॉडल्स और EV लॉन्च पर फोकस कर रही हैं। यह आंकड़ा भारतीय ऑटो इंडस्ट्री की मजबूती और उपभोक्ता विश्वास को दर्शाता है।

IRDAI Proposes Ind AS Adoption for Insurance Sector from April 2026

Shift to Indian Accounting Standards to Enhance Transparency and Global Comparability; Life and General Insurers to Align Financial Reporting with Ind AS Framework

New Delhi: The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has proposed the adoption of Indian Accounting Standards (Ind AS) for the insurance sector, effective from April 1, 2026. The move aims to bring greater transparency, consistency, and global comparability to the financial reporting of insurers, aligning the sector with international best practices.

Under the proposal, both life and general insurance companies will transition from the current statutory accounting framework to Ind AS, particularly Ind AS 109 (Financial Instruments) and Ind AS 117 (Insurance Contracts). These standards require insurers to measure insurance liabilities at fair value, recognise embedded options and guarantees more accurately, and provide detailed disclosures on risk exposure and capital adequacy.

IRDAI Chairperson Debasish Panda said the shift would improve the quality of financial statements, enable better risk assessment by stakeholders, and support the sector's growth in a more transparent manner. The regulator has invited comments from insurers, actuaries, and other stakeholders by February 15, 2026, before finalising the implementation roadmap.

The transition is expected to have a significant impact on reported profits, solvency margins, and investment strategies of insurers. Life insurers may see changes in profit emergence patterns due to the new measurement of long-term liabilities, while general insurers will need to adapt to fair value accounting for short-tail contracts.

Industry experts view the proposal as a progressive step that will attract more foreign investment and strengthen the sector's credibility. However, it will also require substantial investments in IT systems, actuarial modelling, and staff training to ensure smooth compliance. With India's insurance penetration still below 4% and the sector targeting a doubling of premium income by 2030, the adoption of Ind AS is seen as essential for building a more mature, investor-friendly ecosystem. Insurers have been given a transition period to prepare, with phased implementation expected to begin in FY27.

Strait of Hormuz at Risk: How the Israel-Iran Conflict Is Disrupting Global Markets and India's Economy

Global financial and commodity markets are being shaken by the escalating conflict between Israel and Iran, especially after recent strikes in the region that have put the Strait of Hormuz a key global oil transit route under threat. This narrow channel of water, located between the Persian Gulf and the Gulf of Oman, is critical to the world's energy supplies. Nearly 20 million barrels of crude oil and large quantities of liquefied natural gas (LNG) pass through it every day, supplying a significant share of global demand.

What's worrying markets now is the potential disruption of this route. Several oil tankers have stayed out of the strait, and ship insurers have become hesitant to cover shipments amidst the conflict, effectively reducing traffic. Analysts say that even if the strait isn't fully closed, the risk premium on oil prices has already increased significantly, as traders' factor in the possibility of supply interruptions.

As a result, global oil benchmarks such as Brent crude have climbed sharply rising more than 2% recently to above $83 per barrel amid fears of supply disruption. In simple terms, when oil prices rise quickly, the cost of goods and services that depend on fuel from transportation to manufacturing also go up. Higher global energy prices fuel inflation, reduce consumer spending power, and make manufacturing and logistics more expensive.

The impact is being felt not just in oil markets but also in global stock exchanges. Investors tend to move money into safe-haven assets such as gold and U.S. government bonds when political and geopolitical risks increase. At the same time, stock markets worldwide, including in Asia and Europe, have seen increased volatility as traders respond to uncertain energy supplies and inflation concerns.

Indian markets have not remained immune to these global shocks. On the first trading session after the conflict escalated, both the BSE Sensex and the Nifty 50 fell sharply, reflecting fear and caution among investors. Energy companies, airlines, and transportation sectors were especially hit, as higher crude prices directly affect their costs.

For India, the stakes are particularly high because the country imports around 85–90% of its crude oil and a large portion of its LNG, with a major share passing through the Strait of Hormuz. A sustained rise in oil prices increases India's import bill, widens the current account deficit, and can put pressure on the rupee, making imports more expensive. Higher energy costs often translate into broader inflation, slowing economic growth and tightening consumer budgets. Global brokerages now say that if oil prices remain elevated for a longer period, inflation risks could rise and narrow room for monetary easing by the Reserve Bank of India. Even non-energy sectors feel the ripple effect: logistics costs go up, industrial firms face higher input costs, and consumers may spend less on discretionary items.

The conflict's impact goes beyond energy. Disruptions in shipping routes may delay global trade, affecting exports and imports of a wide range of commodities. If threat levels remain high, India may need to explore alternate sources of crude or rely more on other countries such as Russia or the U.S. for supply strategies that can help cushion short-term shocks but may not fully offset global market pressures.

In conclusion, the Israel-Iran conflict and risks around the Strait of Hormuz are a reminder of how interconnected the global economy is. For India, heavily reliant on energy imports, the shockwaves from this crisis could mean higher fuel costs, inflationary pressure, and market volatility. The situation remains fluid, and how long these pressures last will largely determine their impact on everyday prices, investment sentiment, and economic stability.

Dr. Irshad Ahmad Khan

Dixon, Longcheer Finalise Joint Venture Pact to Boost Local Electronics Manufacturing

Partnership to Set Up Large-Scale Facility in India; Targets Higher Local Value Addition, Component Production, and Reduced Import Dependence

New Delhi: Dixon Technologies (India) Ltd and China's Longcheer Technology have finalised a joint venture agreement to strengthen electronics manufacturing in India. The partnership, announced on Thursday, will establish a new manufacturing facility focused on mobile phones, consumer electronics, and key components such as printed circuit board assemblies (PCBAs), displays, and chargers.

The JV aims to achieve higher levels of localisation under the government's Production Linked Incentive (PLI) scheme and 'Make in India' initiative. Dixon, already one of India's largest contract manufacturers for brands like Samsung, Xiaomi, and Motorola, will bring its strong execution capabilities, while Longcheer will contribute advanced technology, R&D expertise, and global supply chain know-how.

This collaboration is a strategic step toward building a more self-reliant electronics ecosystem in India, said Dixon Technologies Chairman Atul B. Lall. By combining our strengths, we will accelerate component manufacturing, reduce dependence on imports, and support global OEMs with cost-effective, high-quality solutions made in India.

The JV is expected to commence operations in phases starting mid-2026, with an initial focus on scaling production for smartphones and IoT devices. The facility will be in an existing industrial cluster in northern India, leveraging proximity to component suppliers and logistics networks.

Industry analysts view the tie-up as timely amid global supply chain diversification away from China and India's push to become a major electronics hub. The country's electronics manufacturing has grown rapidly, with exports crossing ₹4 lakh crore in 2025, but component localisation remains a challenge. The Dixon-Longcheer JV is expected to help bridge this gap.

As India targets $300 billion in electronics manufacturing by 2030, such partnerships are seen as crucial to achieving deeper value addition and global competitiveness in the sector.

जीएसटी अधिकारियों ने ब्रिटानिया पर 6.37 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस लगाया

इनपुट टैक्स क्रेडिट पर विवाद, कंपनी ने कहा- नियमों का पूरा पालन किया, अपील दायर करेगी; FMCG सेक्टर में टैक्स अनुपालन पर नजरें

मुंबई: ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जीएसटी अधिकारियों से 6.37 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस मिला है। यह नोटिस इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के दुरुपयोग और नियमों के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। कंपनी ने बीएसई को दी सूचना में बताया कि यह नोटिस कुछ पुराने लेन-देन पर आधारित है और इसमें ब्याज व पेनल्टी भी शामिल है। ब्रिटानिया ने स्पष्ट किया कि वह जीएसटी नियमों का पूरा पालन करती है और इस नोटिस के खिलाफ अपील दायर करेगी।

ब्रिटानिया के प्रवक्ता ने कहा, हमारी ओर से कोई गलती नहीं हुई है। यह मामला पुराने ITC क्लेम से जुड़ा है, जिसे हम उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाएंगे। कंपनी ने जोर दिया कि इस नोटिस से उसके बिजनेस या फाइनेंशियल पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह कुल राजस्व का बहुत छोटा हिस्सा है। ब्रिटानिया का FY25 में राजस्व 16,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा था।

यह मामला FMCG सेक्टर में टैक्स अनुपालन पर बढ़ती सख्ती को दर्शाता है। जीएसटी अधिकारियों ने पिछले कुछ महीनों में कई बड़ी FMCG कंपनियों पर ITC और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर नोटिस जारी किए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे नोटिस से कंपनियों को अपनी टैक्स फाइलिंग और रिकॉर्ड रखरखाव में और सावधानी बरतनी होगी।

ब्रिटानिया के शेयर बाजार में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। निवेशकों का मानना है कि कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट और निरंतर ग्रोथ से इस तरह के नोटिस का असर सीमित रहेगा। हालांकि, अपील प्रक्रिया में समय लग सकता है। यह घटना जीएसटी व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुपालन की अहमियत को दोबारा उजागर करती है।

GAIL's LNG Cargo from Petronet Slashed to Zero Amid Strait of Hormuz Tensions

Geopolitical Risks Disrupt Supply Chain; GAIL Faces Spot Market Reliance as Winter Demand Peaks, Industry Calls for Diversified Sourcing

New Delhi: GAIL (India) Ltd has seen its contracted LNG cargo from Petronet LNG's Dahej terminal reduced to zero for the current month due to severe restrictions in the Strait of Hormuz, sources in the petroleum ministry and shipping industry confirmed. The narrow waterway, through which nearly 20% of global LNG trade passes, has witnessed heightened security alerts and vessel delays following recent regional tensions, forcing several Qatari and UAE-origin cargoes to be rerouted or deferred.

GAIL, which sources a significant portion of its long-term LNG under the Petronet-administered RasGas and other contracts, was expecting 3–4 cargoes in January to meet peak winter demand from city gas networks and power plants. With the Strait passage effectively blocked or severely delayed for certain vessels, the utility has been compelled to turn to the spot market at significantly higher prices—current Asian spot LNG is trading around $14–15/MMBtu compared to long-term contract prices of $8–10/MMBtu.

Industry officials said GAIL is now in talks with alternative suppliers in the US, Australia, and Africa to secure replacement volumes, but spot purchases are expected to raise the average cost of gas by 20–30% for January–February. This comes at a time when domestic gas demand has surged due to colder weather in northern India and increased industrial offtake.

Petronet LNG, which operates the Dahej terminal, stated it is working closely with shippers and charterers to minimise disruptions and reroute cargoes where possible. However, experts warn that prolonged Strait restrictions could lead to supply tightness and higher spot prices across Asia.

GAIL has maintained that its overall gas supply position remains adequate, supported by domestic production and diversified long-term contracts. As India targets higher LNG imports to meet rising energy needs, the incident highlights the strategic importance of diversifying sourcing routes and building strategic storage to mitigate geopolitical supply risks.

गोदरेज ट्रायोलॉजी ने लॉन्च पर ₹2,000 करोड़ की बिक्री दर्ज की: दक्षिण मुंबई में लग्जरी बाजार में उछाल

प्रीमियम प्रोजेक्ट की जबरदस्त मांग, हाई-नेटवर्थ निवेशकों का भरोसा; मुंबई के लग्जरी रियल एस्टेट में नया रिकॉर्ड, 2026 में और तेजी की उम्मीद

मुंबई: गोदरेज प्रॉपर्टीज का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट 'गोदरेज ट्रायोलॉजी' ने लॉन्च के कुछ ही दिनों में ₹2,000 करोड़ से अधिक की बिक्री दर्ज की है। दक्षिण मुंबई के प्रीमियम इलाके में स्थित यह प्रोजेक्ट लग्जरी सेगमेंट में जबरदस्त सफलता हासिल कर रहा है। गोदरेज ग्रुप ने मंगलवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्रोजेक्ट की मांग इतनी तेज है कि कई यूनिट्स पहले ही बुक हो चुकी हैं।

गोदरेज ट्रायोलॉजी में 3-4 BHK लग्जरी अपार्टमेंट्स, पेंटहाउस और एक्सक्लूसिव सुविधाएं हैं। प्रोजेक्ट की लोकेशन, विश्व स्तरीय डिजाइन और गोदरेज की ब्रांड वैल्यू ने हाई-नेटवर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) और एनआरआई निवेशकों को आकर्षित किया है। कंपनी के अनुसार, औसत बुकिंग वैल्यू ₹8-12 करोड़ के बीच रही, जो मुंबई के लग्जरी बाजार में नया बेंचमार्क सेट कर रही है।

दक्षिण मुंबई में लग्जरी रियल एस्टेट की मांग पिछले दो वर्षों में 40% से अधिक बढ़ी है। महंगे प्रोजेक्ट्स ¬में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, क्योंकि यह क्षेत्र स्थिर रिटर्न और लाइफस्टाइल वैल्यू प्रदान करता है। -गोदरेज प्रॉपर्टीज के एमडी मोहित मल्होत्रा ने कहा, ट्रायोलॉजी की सफलता दक्षिण मुंबई में लग्जरी की बढ़ती मांग और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को दर्शाती है। हम इस मोमेंटम को बनाए रखेंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में मुंबई के लग्जरी सेगमेंट में और तेजी आएगी। उच्च आय वर्ग और विदेशी निवेशकों की रुचि से यह ट्रेंड जारी रहेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर बाजार तेजी । यह सफलता भारतीय रियल एस्टेट में प्रीमियम सेगमेंट की मजबूती को दर्शाती है।

Fertiliser Prices May Rise Amid Escalating Israel-Iran Tensions

Conflict Threatens Global Potash and Phosphate Supply Chains; Indian Farmers Face Higher Input Costs, Potential Subsidy Strain

New Delhi: Fertiliser prices in India and globally could witness a sharp upward revision in the coming months as geopolitical tensions between Israel and Iran intensify, disrupting key supply routes and raw material availability. Industry experts and trade analysts warn that any further escalation—particularly involving the Strait of Hormuz could severely impact the movement of potash, phosphate rock, and ammonia, critical inputs for fertiliser production.

Israel is a major global supplier of potash (through companies like ICL) and phosphates, while Iran plays a significant role in urea and ammonia exports. The Strait of Hormuz, through which nearly 20% of the world's seaborne oil and a substantial portion of fertiliser raw materials pass, has already seen increased naval activity and insurance premiums for vessels. Recent missile exchanges and threats to close the strait have triggered fears of supply bottlenecks like those seen during past Gulf crises.

In India, which imports over 60% of its potash and a large share of phosphates, the impact could be immediate and severe. DAP (Diammonium Phosphate) and MOP (Muriate of Potash) prices have already shown early signs of hardening in spot markets. The government, which provides heavy subsidies on urea and other fertilisers, may face increased fiscal pressure if global prices rise sharply, potentially leading to partial pass-through to farmers.

Fertiliser industry bodies like FAI and IFFCO have urged the Centre to explore alternative sourcing from Canada, Russia, Belarus, and Morocco, while accelerating domestic production under the urea and DAP PLI schemes. Farmers' associations have warned that higher fertiliser costs could reduce sowing in the upcoming rabi season and impact food inflation.

With the rabi crop season approaching and global fertiliser markets already tight, any prolonged disruption in the Middle East could push retail fertiliser prices up by 10–20% within weeks, squeezing farm economics and raising concerns over food security.

हिंदुस्तान जिंक ने वर्जीनिया टेक के साथ MoU साइन किया: सिल्वर रिकवरी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम

खनन से सिल्वर निकासी में नई तकनीक, उत्पादन 20-30% बढ़ सकता है; भारत की सिल्वर आत्मनिर्भरता और ग्लोबल मार्केट में मजबूती

उदयपुर: हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL), वेदांता ग्रुप की प्रमुख कंपनी, ने अमेरिका की प्रतिष्ठित वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया है। इसका उद्देश्य जिंक खनन प्रक्रिया में सिल्वर रिकवरी को बढ़ाना है। यह MoU हिंदुस्तान जिंक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी भारत की सबसे बड़ी सिल्वर उत्पादक है और वैश्विक स्तर पर भी अग्रणी स्थान रखती है।

MoU के तहत दोनों संस्थाएं संयुक्त रिसर्च करेंगी, जिसमें एडवांस्ड मेटलर्जिकल प्रोसेस, AI-बेस्ड एनालिसिस और नई रिकवरी तकनीकों पर काम होगा। वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक हर साल लगभग 600-650 टन सिल्वर का उत्पादन करती है, लेकिन खनन प्रक्रिया में काफी मात्रा सिल्वर बर्बाद हो जाती है। नई तकनीक से रिकवरी में 20-30% सुधार संभव है, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम होगी।

हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा ने कहा, यह साझेदारी हमें वैश्विक स्तर की तकनीक और विशेषज्ञता देगी। इससे हम भारत की सिल्वर जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे और निर्यात में भी बढ़त हासिल करेंगे। कंपनी राजस्थान की अपनी खदानों से जिंक के साथ सिल्वर भी निकालती है और यह MoU सस्टेनेबल माइनिंग के लक्ष्य को भी सपोर्ट करेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को सिल्वर उत्पादन में और मजबूत बनाएगा। वैश्विक सिल्वर मांग सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और EV बैटरी से बढ़ रही है। यह समझौता 'मेक इन इंडिया' और खनिज आत्मनिर्भरता के विजन को मजबूत करता है।

HINDUSTAN ZINC
Zinc & Silver of India

BPCL Bets Big on Petrochemicals with Higher Capex as IOC & ONGC Cut Back

Rs 50,000 Crore Multi-Year Plan to Build Downstream Strength; Shift from Refining Focus Aims to Improve Margins and Capture High-Growth Specialty Chemicals Demandh

Mumbai: Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) is pursuing an aggressive expansion in petrochemicals, significantly raising its capital expenditure (capex) while peers Indian Oil Corporation (IOC) and Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) have signalled more conservative spending in the current fiscal year. BPCL has outlined a multi-year capex plan of approximately Rs 50,000 crore, with a large portion earmarked for building integrated petrochemical complexes and value-added downstream units.

The company is accelerating development at its Bina refinery in Madhya Pradesh and planning new facilities at Bargarh in Odisha. The focus is on producing polypropylene, polyethylene, aromatics, and specialty polymers products that command 2–3 times higher margins than conventional fuels amid persistent pressure on global refining cracks.

BPCL Chairman & Managing Director G. Krishnakumar said the shift is a deliberate strategy to de-risk the business from volatile refining margins. Petrochemicals offer better long-term visibility and profitability. We are moving up the value chain to serve growing demand in packaging, automotive, and infrastructure sectors," he stated.

The increased spending contrasts with IOC's moderated capex guidance and ONGC's focus on upstream exploration and production amid uncertain crude prices. BPCL's move reflects confidence in domestic petrochemical demand, projected to grow 8–10% annually, driven by India's infrastructure push and rising consumption of plastics and chemicals.

Analysts expect the petrochemical thrust to improve BPCL's EBITDA margins by 200–300 basis points over the next 4–5 years and reduce dependence on fuel sales. The company is also exploring partnerships for technology and feedstock security.

BPCL shares rose on BSE, outperforming peers and reflecting investor optimism about the downstream pivot. With India targeting 30 million tonnes of petrochemical capacity by 2030, BPCL's bold investment signals strong belief in the sector's structural growth potential despite near-term refining challenges.

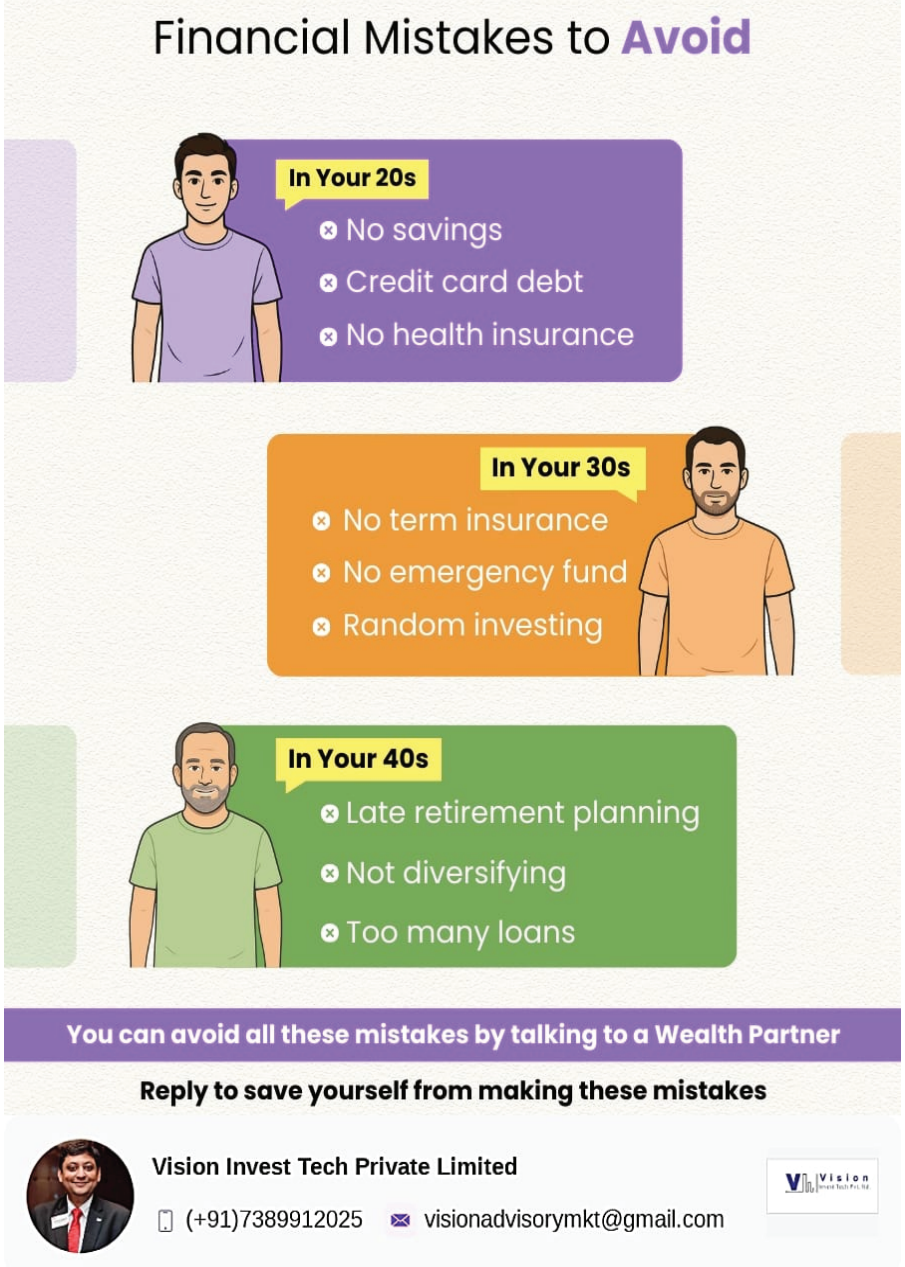

Glenmark Pharmaceuticals Secures USFDA Approval for Fluticasone Inhaler

Generic Version of Flovent HFA to Expand Respiratory Portfolio; Affordable Inhaler Option for Asthma Patients, Boost to US Generics Revenue

Mumbai: Glenmark Pharmaceuticals Ltd has received final approval from the US Food and Drug Administration (USFDA) for its generic fluticasone propionate inhalation aerosol (50 mcg, 125 mcg, and 250 mcg strengths), equivalent to GlaxoSmithKline's Flovent HFA. The approval allows Glenmark to launch the product in the United States, strengthening its position in the high-demand respiratory segment.

Fluticasone propionate is a widely prescribed inhaled corticosteroid used for the maintenance treatment of asthma in patients aged four years and older. The branded version has been a blockbuster drug, with annual US sales exceeding $2 billion before generics entered the market. Glenmark's generic version is expected to offer significant cost savings to patients and payers, improving access to preventive asthma therapy.

This approval is a key addition to our growing respiratory franchise in the US, said Glenmark Pharmaceuticals President & Global Head of Formulations Robert Crockart. We remain focused on delivering high-quality, affordable generics to address chronic conditions like asthma that affect millions of Americans.

The inhaler will be manufactured at Glenmark's facilities in India and marketed through its US subsidiary, Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA. The company already has a strong presence in respiratory generics, with products like budesonide, salmeterol, and montelukast inhalers and nebulizers.

Analysts view the approval as a positive trigger for Glenmark's US generics business, which has been a key growth driver despite pricing pressures. The launch is expected to contribute meaningfully to revenue in FY27, especially as asthma remains one of the most prevalent chronic respiratory conditions globally.

Glenmark shares rose on BSE following the announcement. With the US generics market remaining highly competitive, timely approvals like this reinforce Glenmark's ability to capitalise on patent expiries and deliver value to patients and shareholders. The approval also highlights India's continued strength in supplying affordable, high-quality generics to the world's largest pharmaceutical market.

नटको फार्मा ने अमेरिका में जेनेरिक ब्लड कैंसर दवा लॉन्च की

लेनालिडोमाइड कैप्सूल का जेनेरिक संस्करण, मूल दवा से 70% सस्ता; हजारों मरीजों को सुलभ इलाज, अमेरिकी बाजार में मजबूत स्थिति

हैदराबाद: भारतीय फार्मा कंपनी नटको फार्मा ने अमेरिकी बाजार में ब्लड कैंसर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण जेनेरिक दवा लॉन्च की है। कंपनी ने यूएसएफडीए की मंजूरी के बाद लेनालिडोमाइड कैप्सूल (Lenalidomide Capsules) विभिन्न स्ट्रेंथ्स (2.5 mg से 25 mg) में बाजार में उतार दिया है। यह दवा मूल ब्रांड रेवलिमिड (Revlimid) का जेनेरिक संस्करण है, जो मल्टीपल मायलोमा और मायलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स के इलाज में इस्तेमाल होती है।

नटको के अनुसार, यह जेनेरिक दवा मूल दवा की तुलना में 60-70% सस्ती होगी, जिससे अमेरिका में लाखों कैंसर मरीजों को सस्ता और सुलभ इलाज मिल सकेगा। रेवलिमिड की अमेरिकी बिक्री पहले 10 अरब डॉलर से अधिक थी, लेकिन पेटेंट समाप्त होने के बाद जेनेरिक कंपनियों के लिए बाजार खुल गया है। नटको इस सेगमेंट में पहले से सक्रिय है और इस लॉन्च से उसकी ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो और मजबूत होगी।

नटको के एमडी डॉ. राजशेखर वांगापल्ली ने कहा, यह लॉन्च हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है कि उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाएं। हम अमेरिकी मरीजों को जीवन रक्षक दवाओं तक आसान पहुंच दे रहे हैं। कंपनी के पास अमेरिका में 100 से अधिक एंडा (ANDA) मंजूर हैं और ऑन्कोलॉजी में कई महत्वपूर्ण उत्पाद हैं।

यह सफलता भारत के जेनेरिक दवा निर्यात को नई गति देगी। FY25 में नटको का अमेरिकी बाजार में राजस्व मजबूत रहा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस लॉन्च से कंपनी को 400-600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता है। यह उपलब्धि भारत को वैश्विक जेनेरिक हब के रूप में मजबूत बनाती है।

Embassy REIT Raises ₹1,400 Crore via 10-Year NCDs at 7.49% Coupon

Strong Investor Demand for Long-Term Debt; Funds to Support Debt Repayment, Acquisitions, and Portfolio Expansion in Office Sector

Bengaluru: Embassy Office Parks REIT, India's largest real estate investment trust by market capitalisation, has successfully raised ₹1,400 crore through a 10-year non-convertible debenture (NCD) issuance priced at a coupon rate of 7.49%. The bond, rated AAA by CRISIL and ICRA, was oversubscribed by institutional and high-net-worth investors, reflecting strong confidence in the REIT's stable cash flows and growth prospects.

The NCDs, issued under the private placement route, carry a fixed coupon of 7.49% per annum with semi-annual interest payments. Proceeds will be used primarily for refinancing existing debt, funding strategic acquisitions, and supporting general corporate purposes, including asset enhancement initiatives across its portfolio of Grade-A office parks in Bengaluru, Mumbai, Pune, and Noida.

Embassy REIT CEO Vikaas M. Sachdeva said, "The successful placement demonstrates the market's trust in our resilient business model and long-term value creation potential. This long-tenure funding strengthens our balance sheet and provides flexibility to pursue accretive opportunities in India's fast-growing office real estate market."

The issuance comes at a time when Indian REITs are increasingly tapping bond markets for longer-duration capital to match their stable, annuity-like rental income profiles. With office occupancy levels improving and demand for Grade-A spaces remaining robust driven by IT-ITeS, BFSI, and global capability centres Embassy's portfolio of over 45 million sq ft continues to deliver healthy rental escalations and low vacancy.

Analysts noted that the 7.49% coupon is attractive relative to current market yields and provides a competitive funding cost compared to shorter-tenure debt. The REIT's strong sponsor backing from Blackstone and Embassy Group, along with its consistent distribution track record, further bolstered investor appetite.

As India's commercial real estate sector benefits from structural tailwinds, such capital market access will enable large REITs to accelerate growth while maintaining financial discipline.

एनार लैब्स ने 500 मिलियन डॉलर जुटाए, वैल्यूएशन 3.75 अरब डॉलर: एनवीडिया का समर्थन

ऑप्टिकल I/O तकनीक में क्रांति, AI और डेटा सेंटर्स के लिए नई उम्मीद; भारत में भी सेमीकंडक्टर और AI हार्डवेयर को मिलेगा फायदा

Stock Name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	24450	25542	25265	24858	24581	24174	23897	23490
BANK NIFTY	57783	61882	61030	59406	58554	56930	56078	54454
SENSEX	78919	82409	81520	80220	79331	78031	77142	75842
FINNIFTY	26652	28467	28089	27370	26992	26273	25895	25176
MIDCAP	13167	13958	13704	13436	13182	12914	12660	12392
ACC	1500	1627	1601	1551	1525	1475	1449	1399
AXISBANK	1315	1433	1409	1362	1338	1291	1267	1220
ABCAPITAL	326	369	357	342	330	315	303	288
BHARTIARTL	1872	2043	1986	1929	1872	1815	1758	1701
BHEL	259	287	276	268	257	249	238	230
BIOCON	390	417	405	398	386	379	367	360
BEL	470	512	493	481	462	450	431	419
CDSL	1226	1322	1287	1257	1222	1192	1157	1127
DATAPATTERN	3505	4248	3928	3717	3397	3186	2866	2655
ESCORTS	3281	3713	3606	3444	3337	3175	3068	2906
EICHERMOTOR	7626	8316	8157	7891	7732	7466	7307	7041
FEDERAL BANK	287	312	306	296	290	280	274	264
GRINFRAPOJECT	936	992	967	952	927	912	887	872
HDFCBANK	857	921	904	881	864	841	824	801
HCLTECH	1358	1438	1412	1385	1359	1332	1306	1279
HINDUNILVR	2223	2445	2400	2311	2266	2177	2132	2043
HAL	4028	4319	4179	4104	3964	3889	3749	3674
HYUNDAI	2080	2222	2187	2134	2099	2046	2011	1958
IOC	168	191	187	177	173	163	159	149
ICICIBANK	1315	1427	1403	1359	1335	1291	1267	1223
INFY	1310	1386	1356	1333	1303	1280	1250	1227
ITC	310	324	320	315	311	306	302	297
KOTAKBNK	401	427	421	411	405	395	389	379
LICHOUSING	512	552	543	528	519	504	495	480
LT	3949	4521	4331	4140	3950	3759	3569	3378
LUPIN	2330	2487	2428	2379	2320	2271	2212	2163
MARUTI	14139	15507	15096	14617	14206	13727	13316	12837
M&M	3336	3572	3473	3405	3306	3238	3139	3071
MGL	1047	1351	1289	1168	1106	985	923	802
MAZGAONDOC	2480	3084	2821	2651	2388	2218	1955	1785
PFC	407	458	442	424	408	390	374	356
RECLTD	339	379	365	352	338	325	311	298
RELIANCE	1408	1569	1497	1452	1380	1335	1263	1218
SBIN	1140	1236	1217	1178	1159	1120	1101	1062
SUNPHARMA	1795	1924	1865	1830	1771	1736	1677	1642
SHRIRAMFINANCE	1011	1143	1107	1059	1023	975	939	891
TITAN	4235	4595	4462	4349	4216	4103	3970	3857
TCS	2560	2704	2669	2615	2580	2526	2491	2437
TATAMOTORS	351	400	389	370	359	340	329	310
UPL	628	681	659	644	622	607	585	570
VALIENT	214	253	243	229	219	205	195	181
WIPRO	196	207	203	200	196	193	189	186

नई दिल्ली: अमेरिका की स्टार्टअप कंपनी आयार लैब्स (Ayar Labs) ने 500 मिलियन डॉलर (लगभग 4,200 करोड़ रुपये) की फंडिंग राउंड पूरा कर लिया है। कंपनी की वैल्यूएशन अब 3.75 अरब डॉलर हो गई है। इस राउंड में एनवीडिया (NVIDIA) सहित कई बड़े निवेशकों ने हिस्सा लिया। यह फंडिंग आयार लैब्स की ऑप्टिकल I/O (Optical Input/Output) तकनीक को बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिए है, जो AI चिप्स और डेटा सेंटर्स में क्रांति ला सकती है।

आयार लैब्स की तकनीक पारंपरिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स की जगह ऑप्टिकल (लाइट-बेस्ड) कनेक्शन्स का उपयोग करती है। इससे डेटा ट्रांसफर की स्पीड 10 गुना तेज हो सकती है और बिजली की खपत 90% तक कम हो सकती है। यह तकनीक एनवीडिया जैसे AI चिप मेकर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बड़े AI मॉडल्स और सुपरकंप्यूटर्स में डेटा मूवमेंट सबसे बड़ी चुनौती है।

कंपनी के सीईओ चार्ल्स वॉट्स ने कहा, यह फंडिंग हमें बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और ग्लोबल मार्केट में पहुंचने में मदद करेगी। हमारा लक्ष्य AI और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को अगले स्तर पर ले जाना है। एनवीडिया के अलावा अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, एप्लाइड मटेरियल्स और अन्य बड़े निवेशकों ने इस राउंड में हिस्सा लिया।

भारत के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश सेमीकंडक्टर और AI हार्डवेयर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एनार लैब्स जैसी तकनीक भारत के डेटा सेंटर्स और AI चिप डिजाइन में उपयोग हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फंडिंग ऑप्टिकल कंप्यूटिंग में नई क्रांति लाएगी और भारत को वैश्विक टेक हार्डवेयर में मजबूत बनाएगी।